ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर सरकारी लूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर में वाहनों एवं युवाओं की बढ़ती संख्या के चलते ड्राइविंग लाइसेंस एक अनिवार्यता बन गया है। लोग़ों की इस अनिवार्यता को पहले हुड्डा सरकार ने सरकारी लूट का जरिया बनाया तो अब खट्टर सरकार ने उस लूट की दर में और इजाफ़ा कर दिया।

पहले पुलिस इन्स्पेक्टर या डीएसपी लाइसेंस आवेदक का टेस्ट लेता था, फ़िट पाये जाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी (एसडीएम) लाइसेंस जारी कर देता था। इसके लिये कुल फ़ीस 21 रुपये होती थी। बाद में बढ़ कर 100, 150 तक होती चली गयी। जो अब बढ़ कर 1280 रुपये + रैडक्रास लूट जो समय अनुसार बदलती रहती है। लेकिन अब सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाया जाता है जिसकी सरकारी फ़ीस 650+118 टैस्ट फीस+1000 रुपये रैडक्रास है। इस फ़ीस के अलावा गैरकानूनी रूप से आवेदक की मेडिकल जांच के नाम पर रेड क्रॉस सोसायटी ने अपनी दुकान भी साथ में खोल ली है। सोसायटी की तरफ़ से एक दिखावटी से डॉक्टर द्वारा मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के नाम पर 100 से 200 रुपये तक की वसूली कर ली जाती है। ध्यान रहे कि एक्ट में लर्निंग लाइसेंस के लिये मेडिकल रिपोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये यह वसूली बिल्कुल ही गैरकानूनी है। हां, नियमित लाइसेंस के लिये जरूर मेडिकल कराने का प्रावधान है, परन्तु वह किसी में एमबीबीएस डॉक्टर से कराया जा सकता है, रेड क्रॉस वाले डॉक्टर से कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

खट्टर सरकार ने अपनी इस लूट को और बढाने के लिये प्रत्येक लाइसेंस आवेदक को पहले रेड क्रॉस में एक हज़ार रुपये की पर्ची कटा कर एक सप्ताह तक प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग लेनी होगी, फ़िर वहां से प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर लाइसेंस हेतु आवेदन स्वीकार किया जायेगा। उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा आयोजित टैस्ट पास करने के बाद आवेदन एसडीएम कार्यालय पहुंचता है। वहां से फ़िर लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

लगभग ऐसी ही फ़जीहत लाइसेंस के नवीकरण के समय भी होती है। बीसियों साल पुराने लाइसेंस का नवीकरण कराने से पहले रेड क्रॉस की एक हज़ार वाली पर्ची, वही एक सप्ताह की ट्रेनिंग का नाटक। इसके लिये आवेदक को आना होगा सेक्टर 12 स्थित सोसायटी के कार्यालय। यहां से निपटने के बाद एसडीएम कार्यालय बल्लबगढ या बडखल जैसी भी स्थिति हो। एसडीएम कार्यालय में नवीकरण की फ़ीस कटती है 650 रुपये, यदि एक दिन भी लेट हो जाये तो लेट फ़ीस ग्यारह सौ रूपए, एक वर्ष से अधिक हो जाय तो 2200 रुपये की लेट फ़ीस लगती है।

हां यदि दफ़तरों व रेडक्रॉस सोसायटी के चक्कर काटने या ट्रेनिंग के ड्रामे से कोई बचना चाहता है तो दलालों की सेवा हाजिर है। इसके लिये मात्र 3000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। उसके बाद आवेदक को मात्र एक बार एसडीएम कार्यालय आना होगा कम्प्यूटर पर फ़ोटो खिचाने के लिये वह भी दलाल द्वारा दिये गये निश्चित समय पर केवल 10-15 मिनट के लिये। संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि रेड क्रॉस सोसायटी सीधे ज़िला उपायुक्त के अधीन होती है। उनकी पत्नी ज़िला स्तर पर इसकी चेयरमैन होती है। इसके बदले उन्हें सोसायटी की ओर से एक कार भी घूमने फ़िरने को मिलती है। कार के अलावा और भी अनेकों प्रकार के उनके खर्चे सोसायटी वहन करती है। ज़िला उपायुक्त की प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग के बल पर ही सोसायटी आम जनता को लूटती है।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100,500 रुपये 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में
खाता संख्या : 451102010004150
IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

भाजपा की मोदी सरकार सरकारी उपक्रमों को अर्थहीन व बर्बाद करने पर तुली

मज़दूर मोर्चा के 21-27 अक्तुबर 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में राजनीति की दखलंदाज़ी नहीं होनी चाहिये क्योंकि राजनीतिक दखलंदाजी व चंदे की एकत्रित राशि में हिस्सेदारी के कारण अपना-अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश से संस्थाओं में गुटबाज़ी हो जाती है।

'अभूतपूर्व' दशहरा: अधर्म की अधर्म पर जीत! दशहरा मैदान में दो मंत्रियों की नहीं, दो प्रोपर्टी डीलरों की लड़ाई में बेनकाब सबसे अनुशासित पार्टी का दम भरने वाली भाजपा के चेहरे पर पुती कालिख' से एनआइटी फ़रीदाबाद के दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में मंच पर भाजपा के केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर व भाजपा विधायक सीमा त्रिखा और हरियाणा के भाजपा मंत्री विपुल गोयल तथा मीरापुर (यूपी) से भाजपा सांसद अवतार सिंह भड़ाना के बीच तू-तू-मैं-मैं व लड़ाई का तमाशा उज़ागर हआ है। कृष्णपाल तथा विपुल गोयल दोनों ने दशहरा के मंच पर जनता के सामने व्यक्तिगत महाभारत की और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुये ऊंची आवाज़ में एक दूसरे पर उंगली तान कर बात की। दोनो मंत्रियों के व्यक्तिगत राजनीतिक व आर्थिक हित आड़े आ रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं में राजनीतिक दखलंदाज़ी व इस दशहरा प्रकरण ने अनुशासन का दंभ भरने वाली भाजपा के मुंह पर कालिख पोत दी है तथा पर्दाफ़ाश हो गया कि भाजपा के मंत्री तथा नेता अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

भाजपा की मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करके निजी संस्थाओं को बढावा देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा की खट्टर सरकार ने हरियाणा रोडवेज की परिवहन व्यवस्था को पंगु बनाकर प्राइवेट पूंजीपतियों को प्राइवेट बसें चलाने का लाइसेंस देने पर उतारू है, जिसका 'हरियाणा रोडवेज की हड़ताल, सरकार की खड़ताल, यात्री बेहाल' में स्पष्ट किया गया है। हरियाणा रोडवेज़ में बसें तो हैं परंतु ना तो बसों को चलाने के लिये नियमित ड्राइवर का कंडक्टर भर्ती किये जाते हैं और न खराब हुई बसों की मरम्मत करने के लिये मिस्त्री। इनकी बजाए ठेके पर भर्ती करके कच्चे कर्मचारियों से काम चलाने की कोशिश की जाती है जिनको बस चलाने का आवश्यक अनुभव व कौशल नहीं होता। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी इस सरकारी उपक्रम को सरकार द्वारा निजीकरण के कुचक्रों से बचाने व अपनी सेवा-शर्तों में सुधार के लिये हड़ताल पर हैं जिनको हरियाणा के अन्य कर्मचारी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त है। सरकार के झूठे आश्वासनों के कारण भी कर्मचारी नाराज हैं।

पुलिस द्वारा अपराधियों के मारे जाने के बावजूद न तो अपराधिक वारदातों में कोई कमी आ रही है और न अपराधियों की संख्या में कमी। आम लोग व समाज बढते अपराधों के लिये पुलिस को दोषी ठहराते हैं और पुलिस व्यवस्था को निकम्मी व भ्रष्ट मानते हैं। लेकिन समाज में बढ़ते अपराध के लिये सामाजिक व राजकीय व्यवस्था दोषी है जिसमें शिक्षा से आम जनता को वंचित किया जा रहा है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को पंगु बनाकर निजी संस्थाओं को बढावा दिया जा रहा है, जिसका 'खूंखार अजय गूजर की गिरफ़्तारी पर खुश होने की जरूरत नहीं -शिक्षा एवं रोजगार के अभाव में नित्य पैदा हो रहे हैं खूंखार अपराधी' में सटीक विश्लेषण किया गया है। भाजपा की खट्टर सरकार की लच्चर शिक्षा नीति ने हरियाणा शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया जबकि इसकी तुलना में केरल की शिक्षा व्यवस्था कहीं बेहतर है जिसके कारण केरल के शिक्षित युवक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं।

'अखंड भारत का जाप करने वाले इसे खंडित करने पर तुले हैं-कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं चाहते भारत-पाक की जनता के बीच मधुर संबंध हो' में एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तथ्यों सहित वास्तविकता को स्पष्ट किया है कि पूर्वी पंजाब जो भारत का अभिन्न अंग है तथा पश्चिमी पंजाब जो अब पाकिस्तान का भाग है दोनो के लोगों की संस्कृति, खाना, भाषा, जीवन शैली लगभग एक जैसी है परंतु दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडू आदि के लोगों की जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। यदि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में जाता है तो वह वहां अपने आप को असहज महसूस करता है। इसलिये पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का अपने खिलाड़ी मित्र इमरान खान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और पाकिस्तानी जनरल बाजवा से गले मिलने के बाद भारत आकर उचित ही कहा कि पाकिस्तान की संस्कृति, बोल-चाल, खान-पान व रहन-सहन बिल्कुल उनके (पंजाब) जैसा है जबकि दक्षिण भारत का सब कुछ उनसे भिन्न है। भारत व पाकिस्तान के आम लोग तो एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं परंतु दोनों देशों के कट्टरपंथी अपने राजनीतिक व धार्मिक मंसूबों के कारण भारत-पाक की जनता के बीच मधुर संबंध नहीं चाहते।

यूपी में भाजपा की योगी सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का सरकारी कार्यक्रम बिल्कुल तर्कहीन व अर्थहीन है। प्रयाग पहले एक तीर्थस्थान था जहां कुछ मंदिर व पुजारी थे और मुनियों के आश्रम थे लेकिन वहां कोई नगर नहीं था। अकबर ने नगर की नींव डाली और वहां किला और बांध बनवाया, जिससे एक नगर आबाद हुआ और लोग उसे ''इलाहाबास'' के नाम से जानने लगे। 'इलाहाबाद शहर के वास्तविक संस्थापक थे सम्राट अकबर!' में तथ्यों और तर्कों से पाठकों को इलाहाबाद की वास्तविकता से परिचित कराने का साहसिक कार्य किया गया है।

भाजपा की मोदी सरकार सरकारी उपक्रमों को अर्थहीन व बर्बाद करने पर तुली हुई है। राफ़ेल डील के समय सरकारी कंपनी एचएएल को नज़रंदाज करके सरकार ने अपने पूंजीपति मित्र अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को तरजीह दी। उस समय सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि एचएएल के पास समय का आभाव है इसलिये राफ़ेल लड़ाकू विमान तैयार करने में देरी होती। लेकिन एचएएल के मामले में एक दिलचस्प रहस्योद्घाटन हुआ है कि एएचएएल के पास अब कुछ खास काम नहीं है, क्योंकि उसके पास आर्डर की कमी है। इस कारण कंपनी के हज़ारों कर्मचारियों को महिनों तक बिना काम के खाली बैठने का डर सताने लगा है। अब मोदी सरकार मुनाफ़ेवाली सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक सरकारी कंपनी ओएनजीसी को घाटे वाली कंपनी बनाने पर उतारू है, जिसका 'सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों को एक-एक कर ठिकाने लगाया जा रहा है' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

यूपी की योगी सरकार व स्वयं मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में धर्म व जाति की राजनीति खेलने में और लोगों का ध्यान बिगड़ती कानून-व्यवस्था से भटकाने में लगे हैं। अब कुछ समय से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के मुद्दे पर लोग़ों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रदेश के रिहाई मंच ने पिछले 20 दिनों में हुई वारदातों को 'योगी बतायें सूबे के बद्तर हालात के लिये कौन सा मुगल शासक जिम्मेदार- रिहाई मंच ने जारी की कानून व्यवस्था की पोल खोलती पिछले दिनों की घटनाओं की फेहरिश्त' के जरिए उज़ागर करके योगी सरकार की कानून-व्यवस्था व लच्चर प्रशासन व्यवस्था की पोल खोली गई है।

मोदीजी ने 2014 में जनता के अच्छे दिनों के शब्जबाग दिखाकर सत्ता पर कब्जा किया था लेकिन अपने साढे चार साल के कार्यकाल में उन्होंने न तो जनता से किए वादे पूरे किए और न कोई ऐसा काम किया जिसमें सरकारी विभागों में जनता के धक्के कम हो जाये, जिसका 'अच्छे दिन नहीं जी, बुरे दिन आने वाले हैं....मोदी के!' में पर्दाफ़ाश किया गया है। मोदीजी के अन्धभक्त जरूर मोदीजी की लोकप्रियता का गुणगान कर रहे हैं, परंतु आम आदमी मोदीजी की नीतियों व पूंजीपति मित्रों के प्रति रूझान के कारण परेशान है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह और मोदीजी ने अपने आईटी सैल के कार्यकर्ताओं को मोदीजी का गुणगान करने और उनके कार्यों की झूठी खबरें प्रसारित करने के लिये प्रेरित किया है तथा मोदीजी ने अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिये लोग़ों को 2022 के सपने दिखाने शुरू कर दिये हैं।

आगामी चुनाव में कांग्रेस द्वारा गरीब मतदाताओं से भाजपा की बजाये उसे जीताने की अपील करने पर 'सुन! अब मुझे मौका दे....', एनआईटी के विधायक नगेन्द्र भड़ाना व शिव टूल्स एंड इंजिनियरिंग के मालिक भोकम सिंह बघेल द्वारा श्रमिक माया को धोखे में रखकर नकली समझौता करवाने पर 'खुला भेद' तथा मोदीजी द्वारा अच्छे दिन आएंगे का वादा पूरा न होने पर 'तो क्या आ गये अच्छे दिन??? आ जाऊं बाहर....!!' कार्टूनों के जरिये उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।